

Saarth E-Journal of Research

E-mail : sarthejournal@gmail.com
www.sarthejournal.com

ISSN NO : 2395-339X
Peer Reviewed
Vol.8 No.20

Impact Factor
Quarterly
Jan-Feb-Mar 2023

भ्रष्टाचार और युवा

प्रो. ललीतभाई डी. चावडा

प्रस्तावना:

भ्रष्टाचार. का शाब्दिक अर्थ है-गिरा हुआ व्यवहार । स्वार्थ और लोभ के कारण किया गया अमानवीय व्यवहार भ्रष्टाचार कहलाता है । कुछ लोग घूस, मिलावट आदि गलत कार्यों को ही भ्रष्टाचार की संज्ञा देते हैं। परंतु यह भ्रामक धारणा है । भ्रष्टाचार का दायरा बहुत बड़ा है। प्रधानमंत्री से लेकर चपरासी तक इसका फैलाव है। अगर प्रधानमंत्री अपनी कुर्सी के लिए लोगों में फूट डालता है, किसी विशेष वर्ग के प्रति पक्षपात और अन्य के प्रति उपेक्षा रखता है तो वह भ्रष्टाचारी है। अगर राजनीतिज्ञ वोट पाने के लिए समाज को गुमराह करता है, डॉक्टर अधिक धन के लालच में रोगी का ठीक उपचार नहीं करता, इंजीनियर ठेकेदारों से साँठगाँठ करके कमजोर पुल बनाता है। प्रोफेसर कक्षा में ठीक से न पढ़ाकर घर में ट्यूशन पढ़ाता है, परीक्षक छात्रों को नकल करवाता है, विद्यार्थी नकल करके उत्तीर्ण होता है, व्यापारी मिलावट करता है या मनचाहे दाम लेता है या कम तोलता है, पुलिस का जवान अपराधी को नजरअदाज करता है, दफ्तर का बाबू दफ्तर का काम समय पर न करके ओवरटाइम करता है, आफिसर रिश्वत लेता है, चपरासी सोया रहता है, सरकारी कर्मचारी ठीक पैसे वसूलने की बजाय बीच में पैसे खाता है तो यह सब प्रष्ट आचरण हैं । यह अमानवीय व्यवहार है, क्योंकि इससे समाज का अहित होता है। भारत में आज सर्वत्र भ्रष्टाचार का बोलबाला है । जीवन का कोई ऐसा क्षेत्र नहीं रह गया है, जिसमें ईमानदारी से कार्य होता है। बच्चे के जन्म से प्रारंभ कीजिए। सरकारी अस्पतालों में गरीबों के लिए जगह नहीं होती, जबकि अमीरों को शीघ्र दाखिल कर लिया जाता है । प्राइवेट डॉक्टरों की मोटी फीस ही उनके भ्रष्ट आचरण की

कहानी कहती है। आज बाजार में नकली दवाइयों का बोलबाला है। कई बार इंजेक्शन की जगह दूषित पानी भरा रहता है, जो रोगी की जान लेकर छोड़ता है।

मैं सर्वप्रथम उन माताओं को नमन करता हूँ जिन्होंने ऐसे वीर पुत्रों को जन्म दिया जिन्होंने मातृभूमि के लिए अपनी जाने दे दी। भारत का इतिहास गौरवशाली रहा है। इतिहास साक्षी है कि कुर्बानी हमेशा युवाओं ने ही दी है। मातृभूमि की रक्षा में कितनी माताओं की गोद सूनी हो गयी, कितनी बहिनों के भाई उनसे छिन गए एवं कितने ही सिन्दूर उजड़ गए। इस देश का इतिहास इतना गौरवशाली रहा है परंतु आज ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे भारत के युवाओं में एक ठहराव सा आ गया है। हम भगतसिंह, चन्द्रशेखर आजाद, राजगुरु, झांसी की रानी इत्यादी की कुर्बानियों को कभी नहीं भूल सकते हैं। इन वीर सपूतों को भी अच्छा खाना, अच्छा पहनना, घूमना पसन्द होगा परंतु इन्होंने जिस वीरभूमि पर जन्म लिया था उस मातृभूमि की खतिर हंसते हंसते अपने प्राणों को न्यौछावर कर दिया। क्या आज किसी माता की कोख से कोई देश भक्त जन्म लेता है? ऐसा नहीं है पर आज हमारी शिक्षा व्यवस्था के दोष के कारण ही युवा निरंतर पथ भ्रष्ट हो रहा है।

जिस और जवानी चलती है उस और जमाना चलता है।

तलवारों की धारों पर इतिहास हमारा पलता है ॥

वास्तव में माता ही शिशु की प्रथम पाठशाला होती है अर्थात् निश्चित रूप से माँ के संस्कार ही बच्चों में आते हैं। माता जीजाबाई की शिक्षा के कारण छत्रपति शिवाजी जैसे वीर इस धरती को मिले हैं परंतु आज हाय, हैलो की संस्कृति हमारे देश व उसकी संस्कृति को खोखला कर रही है। पश्चिमी देश जो भारत को फलता फूलता नहीं देखना चाहते हैं क्योंकि भारत वर्तमान समय में एक बड़ी शक्ति के रूप में उभर रहा है। दूसरे देशों ने हमारे देश पर सांस्कृतिक हमले शुरू कर दिए हैं। वह जानते हों भारत को रण क्षेत्र में परास्त नहीं कर सकते। इसीलिए उन्होंने सांस्कृतिक गुलामी की जंजीरों में हमारे देश के युवाओं को जकड़ने का एक तीव्र अभियान चला रखा है।

टी.वी. विभिन्न चैनल के माध्यम से आई.टी. के माध्यम से देश हमारे देश के युवाओं में विष घोल रहे हैं। वास्तव में हमारे देश के युवक युवतियां थ्रीडी कल्चर (ड्रेस, ड्रग, डांस) में फँसकर पश्चिमी सभ्यता को बढावा दे रहे हैं। जरा विचार करें कि क्या गांधीजी ने इसी रामराज्य की कल्पना अपने देश में की थी? क्या झांसी की रानी ने अपनी कुर्बानी इसीलिए दी थी कि आगे चलकर हमारे देशकी तरुणाई पश्चिमी सभ्यता का अंधानुकरण करें।

वास्तव में हमारे देश में प्रतिभा की कमी नहीं है। परंतु विश्व को शून्य का ज्ञान कराने वाला ये भारत निरंतर दरिद्र होता जा रहा है। इसका सिर्फ एक ही कारण है युवाओं का संवेदन शून्य होना। आज हम पढ़ लिखकर अच्छे डॉक्टर - इंजीनियर हो जाते हैं। क्या हमारा फर्ज नहीं बनता है कि अपने साथ-साथ इस मातृभूमि के लिए भी कुछ करें जिसकी पवित्र मिट्टी में चलकर हम बड़े हुए हैं।

चन्दन है उस देश की माटी, तपो भूमि हर ग्राम है ।

हर बाला देवी की प्रतिमा, बच्चा-बच्चा राम है ॥

आज हमारा देश भ्रष्टाचार से त्रस्त है चाहे वह कोयला स्पेक्ट्रम, आदर्श सोसायटी घोटाला इत्यादि हर तरफ से मुक्ति नहीं चाहता है । इसके अतिरिक्त जब हम अपनी बहिन व बेटी का संघर्ष करते हैं तो हमारा वेतन नहीं उपरी आमदनी पूछते हैं । उसी के अनुसार दहेज तय होता है । इसके साथ साथ अब तो मूल परीक्षण भी आम चलन है । अगर लडकी है तो गर्भपात निश्चित है । आज व्यक्ति कितना स्वार्थी हो गया है । हमने विश्व को को वसुधैव कुटुम्बकम् कहा है, परंतु आज व्यक्ति सिर्फ अपने बारे में ही सोचता है देश की परवाह किसी को नहीं है ।

वतन की जो हालत बताने लगेंगे ।

तो पत्थर भी आंसू बहाने लगेंगे ॥

ऐसी विषम परिस्थितियों में यदि देश का युवा सोता रहा तो इसके गंभीर परिणाम होंगे । इसे सबसे पहले भ्रष्टाचार, सांस्कृतिक हमलों से सावधान होना पड़ेगा एवं अच्छी शिक्षा ग्रहण कर उस शिक्षा का सही उपयोग और उसके साथ साथ देश के विकास में भी अपना योगदान करना चाहिए ।

भ्रष्टाचार की जड़ें इतनी मज़बूत क्यों हैं?

भारत में भ्रष्टाचार की जड़ें **पीछे की ब्रिटिश उपनिवेशिक राज** के दौरान ही से जुड़ी हुई हैं ब्रिटिश प्रशासन जिसने योजनाबद्ध तरीके से भारतीय आबादी को मुख्य राजनीतिक एवं प्रशासनिक गतिविधियों से बाहर कर रखा था, उन्होंने महत्वपूर्ण **ऑफिशियल सीक्रेट ऐक्ट, 1923** अधिनियम के ज़रिए इस भ्रष्टाचारी संस्कृति को संस्थागत करने में काफी मदद की. इस औपनिवेशिक धारा ने किसी भी सरकारी अधिकारी द्वारा राजकीय सूचना या संदेश को जगजाहिर करना कानूनन अपराध घोषित किया. इस कार्यवाही ने स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात भी इस भ्रष्टाचारी/रिश्वतखोरी की संस्कृति को जीवित बनाए रखने में काफी महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है जबकि भारत पहले से ही ज्यादा कट्टर स्वभाव वाले राजकीय अधिनियम की वजह से इस भ्रष्टाचारी संस्कृति की मकड़जाल में फंस चुका था खासकर, जब बात आर्थिक गतिविधियों पर आयी, जिसने कुख्यात **परमिट लाइसेन्स राज** नाम की विकृति को पैदा किया. ये परमिट राज, जिसने विदेशी निवेश पर लगाम लगाई और “सोशलिस्ट ईकानमी” के नाम पर लोगों के भीतर बसी प्रतिद्वंद्विता की भावना को दबाने का काम किया, जिसने अंततः रिश्वतखोरी की संस्कृति को बढ़ावा देने और सरकार या किसी व्यापारी (वेंडर) से सेवा खरीदने के एवज़ में किराया प्राप्त करने की गतिविधि को प्रोत्साहित किया. इसने हरेक चीजों के लिए एक काला बाज़ार तैयार किया जिससे आयातित वस्तुओं की तस्करी एक आम प्रचलन बन गई.

1991 में शुरू हुई आर्थिक सुधार और उदारीकरण के बाद से भारत की इस भ्रष्टाचार की संस्कृति, देश के लिये बदलाव का मोड़ या टर्निंग प्वाइंट साबित हुआ एक तरफ़ इन

सुधारों ने औद्योगिक गतिविधियों की लाइसेन्सिंग और आयात कोटा के उन्मूलन का अंत किया, जिसके चलते, कई भ्रष्ट तौर तरीकों के हटाए जाने के बावजूद, भ्रष्टाचार को कम नहीं किया. उसके विपरीत, आर्थिक सुधार और ज्यादा उत्पादन ने भ्रष्टाचार की संभावनाओं के दरवाजे को और खोल दिया. कौतूहलवश, किराया/पैसा लेने की प्रवृत्ति के कई रचनात्मक अवतार बन गए. एक तरफ जहां आर्थिक उदारीकरण ने विशेष कर लाइसेन्स पर्मिट राज से संबंधित, पुराने तरीकों से चले आ रहे भ्रष्टाचार को खत्म करने का काम किया, इसके बावजूद वो प्रचलन आज भी किसी न किसी आकार या रूप में कई अन्य विभागों में, खासकर के खनिज पदार्थ, प्राकृतिक संसाधन, और अन्य सेवाओं में, बदस्तूर जारी है. उदाहरण के लिए, कोल ब्लॉक का अपारदर्शी एवं मनमाना आवंटन और (2जी के नाम से बदनाम) टेलीकॉम स्पेक्ट्रम, जिसने राज्य के खजाने तक को हिला कर रख दिया था, स्पष्ट तौर पर सुधार उपरांत के भ्रष्टाचार की भयावहता को बयान करता है. इतना ज्यादा कि संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन (UPA)-II (2019-14) को अपना ज्यादातर समय भ्रष्टाचार की सूची से लड़ने में ही व्यतीत करना पड़ा. इस लंबी कहानी को छोटी करते हुए हम यही कह सकते हैं कि, हालांकि भारतीय अर्थव्यवस्था के कई प्रमुख सेक्टरों में उदारीकरण किए जाने के बावजूद, उसमें ज़रूरी राजनीतिक एवं प्रशासनिक सुधार समाहित नहीं किये गये हैं. ज्यादातर प्रशासनिक एवं विवेकाधीन शक्तियां अब भी सरकारी अधिकारियों के पास ही हैं, जिस वजह से सत्ता का दुरुपयोग एवं रिश्वतखोरी बदस्तूर जारी है

भ्रष्टाचार दूर करने के उपाय :-

1. लोकपाल कानून लागू करने के लिए आवश्यक है
2. संक्षिप्त और कारगर कानून हो
3. जिसे मैं अपने शपथ के साथ शुरू करू कि न तो रिश्वत ले और न ही रिश्वत दे.
4. प्रशासनिक मामलों में पारदर्शिता बनाए और जनता को भागीदार बनाए.
5. न्यायालय में मामला त्वरित निपटारा हो.
6. प्रशासनिक काम यह उपयोगी बनाने के लिए आवश्यक है, लोकपाल स्वतंत्र रूप से कार्य करता रहे.

कानून और सरकार पर से लोगों की मानसिकता बदलने की आवश्यकता है.

सारांश

सारांश में, एक तरफ जहां भ्रष्टाचार जड़ों में गहरा समाया हुआ और अंतहीन है, भारत का भ्रष्टाचार विरोधी उपाय धीमा और आधा- अधूरा ही रह गया है. ऐसा सिर्फ इसलिए हुआ क्योंकि भ्रष्टाचार से लड़ने के लिए बनाए गए उन प्रमुख संस्थानों में स्वायत्ता और उद्देश्य के प्रति गंभीरता की काफी कमी रही. यहाँ तक की चंद मुट्ठीभर भ्रष्टाचार विरोधी संस्थानें (सीवीसी, लोकपाल) जिनके पास किसी हद तक स्वायत्ता थी, उन्होंने भी

स्वतंत्र व स्वायत्त होने के एक भी लक्षण नहीं दिखाये. हालांकि, व्याप्त भ्रष्टाचार से लड़ाई अकेले इन मुट्ठीभर एलीट और बड़े संस्थानों तक ही सीमित नहीं किया जाना चाहिए. ऐसा इसलिए क्योंकि, ऊपरी स्तर पर भ्रष्टाचार के जो मामले होते हैं या सामने आते हैं वो अक्सरहाँ मीडिया की नज़र में आ जाता है और कभी-कभी राष्ट्रीय आक्रोश बन जाता है, लेकिन ज्यादातर भ्रष्टाचार के मामले निचले और मध्यम स्तर पर होते हैं, जो आम आदमी को प्रभावित करता है और वो खुदरा स्तर पर ही होता है. एक तरफ जहां CVC ग्रुप सी, और ग्रुप डी स्तरीय अधिकारियों को शामिल करके इन शिकायतों की जांच करती है, इसके बावजूद सभी प्रतिकूल व व्यवहारिक वजहों से, CVC एक दंतहीन संस्थान ही साबित हुई है. नीचे के स्तर पर हो रहे भ्रष्टाचार को कम करने के लिए जो इकलौता विकास नज़र आता है, वो है सेवाओं का डिजिटलाइजेशन. हालांकि, सिर्फ टेक्नॉलजी की मदद से भ्रष्टाचार की परंपरा को खत्म नहीं किया जा सकता जो कि हाइड्रा-हेडेड दानव है जिसके एक ज़्यादा सिर है.

सार में ये कहा जा सकता है कि, भ्रष्टाचार से लड़ने के लिए ठोस आधारभूत सुधार और मौजूदा कानूनों का व्यापक संशोधन किए जाने की ज़रूरत है. इसके साथ ही, भारत की व्यवस्था को भी सुधारे जाने की आवश्यकता है, जो कई तरीकों से, भ्रष्टाचार की वास्तविक जननी के तौर पर कार्य करती है. बड़े आकार के स्कैंडल, दंडमुक्ति को प्रोत्साहन और मज़बूत भ्रष्ट आचरण जैसे केस एवं मुकद्दमों के समाधान में कई वर्ष एवं दशक लग रहे हैं. उसी तरह से, ये सर्वविदित है कि, भारत में ज्यादातर भ्रष्टाचार और रिश्वतखोरी के मामले आदि अस्पष्ट राजनैतिक फंडिंग (जो की वर्तमान समय में स्पष्ट चुनावी बॉन्ड की अनुमति देने के प्रचलन से ज़ाहिर होता है). सारांश में, वित्तीय सुधार अभियान में बड़े सुधार - खासकर के पारदर्शिता, डिसक्लोज़र और ज़िम्मेदारी - के बगैर, अर्थव्यवस्था और समाज की जड़ों में गहरे तक समाये भ्रष्टाचार को काट पाना मुश्किल होगा. इसलिए, जबकि भारत एक ज़िम्मेदार वैश्विक खिलाड़ी (एक्टर) के तौर पर खुद को स्थापित करने का ध्येय रख रहा है तो, राजनीतिक नेतृत्व के लिए ये ज़रूरी हो जाता है कि वे राजनैतिक फंडिंग में पारदर्शिता लाने के साथ ही व्यापक राजनीतिक सुधार लाना अत्यंत ज़रूरी हैं. इसके अलावा अदालतों से न्याय मिलने की प्रक्रिया में सुधार और आरटीआई की प्रक्रिया को मज़बूत रखना भी भ्रष्टाचार के खिलाफ़ की जाने वाली लंबी लड़ाई में एक महत्वपूर्ण कदम होगा. अब धीरे-धीरे इसके खिलाफ़ अवाज़ बुलन्द होने लगी है, आन्दोलन खड़े होने लगे हैं। इन आन्दोलनों के सबसे बड़े सहभागी हैं हमारे देश के युवा। हाल के वक्त में युवाओं ने जिस तरह से भ्रष्टाचार के खिलाफ़ अपनी विचारधारा को खुल कर जाहिर किया है, आन्दोलनों में खुल कर हिस्सा लिया है और उन लोगों को जगाने का काम किया है जिन्होंने सब कुछ जानते हुये भी अपनी आंखें मूंदी हुयी थीं वो वाकई एक नई सुबह की ओर इशारा करता है। किसी देश की रीढ़ होते हैं युवा, हमारा देश तो वैसे भी युवाओं का देश कहलाता है, जहां पर 60 फीसदी से ज्यादा जनसंख्या युवाओं की है। वैसे भी आने वाली पीढ़ी युवाओं की

ही होती है और अगर युवा किसी आचार को, विचार को या फिर संस्कार को बदल ले तो वो भविष्य के पटल पर दिखायी देने लगता है। भ्रष्टाचार के खिलाफ मुहिम की बागडोर भी युवाओं के हाथों में ही सुरक्षित कही जा सकती है। यही पीढ़ी इसे अंदाम तक ले जा सकती है।

हमारे प्रधानमंत्री नरेन्द्रमोदीजी भ्रष्टाचार रहित भारत की कल्पना कर रहे हैं । लेकिन भ्रष्टाचार रहित भारत कर पाएंगे ? हां हां यदि देशका प्रत्येकनागरिक अपने कर्तव्योंका पालन ईश्वरको साक्षी मानकर करेगा तो प्रधानमंत्रीजी की कल्पना सच होगी । भारत भ्रष्टाचार रहित बनेगा और निश्चित रूपसे भारत विश्वगुरु बनेगा इसमें संदेह नहीं हैं ।

जो भरा नहीं है भावों से
जिसमें बहती रसधार नहीं।
वह हृदय नहीं पत्थर है
जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं ॥

प्रो. ललीतभाई डी. चावडा

(संस्कृत विभाग)

सी.बी. पटेल आर्ट्स कॉलेज,

नडीआद